

जनसत्ता, दिल्ली

5 MAY 2013

मध्यप्रदेश में चल रहे आजीविका कार्यक्रमों को कई देशों ने सराहा

भोपाल, 4 मई (भाषा)। मध्यप्रदेश में जिला गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (डीपीआइपी) के दूसरे चरण की सफलता से दुनिया के कई देशों ने प्रेरणा ली है।

विश्व बैंक की पहल पर पिछले वर्षों में वियतनाम, लाओस और नेपाल से आए प्रतिनिधिमंडलों ने प्रदेश के विभिन्न जिलों का भ्रमण किया और डीपीआइपी के बेहतर अमल से सुदूर अंचलों के गरीब ग्रामीणों के जीवन में आई समृद्धि और आर्थिक बदलाव को देखा। इसी परिप्रेक्ष्य में विश्व बैंक के वाशिंगटन, अमेरिका स्थित मुख्यालय से विगत जून, 2011 में प्रबंध संचालक नागजी ओकोजो इविएला और नवंबर, 2011 में प्रबंध संचालक मेहमूद गोहीउद्दीन ने भी डीपीआइपी के जरिए गरीब ग्रामीणों के जीवन को बेहतर बनाने के कार्यों का जायजा लिया था और इसकी सराहना की थी।

मध्यप्रदेश में डीपीआइपी के दूसरे चरण के क्रियान्वयन के लिए विश्व बैंक के जरिए 110 मिलियन डालर की आर्थिक सहायता मुहैया हुई है। इसमें राज्य सरकार का 10 मिलियन डालर का अंशदान शामिल है। विश्व बैंक के भारत स्थित कंट्री डायरेक्टर ओनो रुहल ने शुक्रवार को रायसेन जिले के गैरतगंज विकास खंड के ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर डीपीआइपी के

जरिए संचालित आजीविका गतिविधियों का जायजा लिया और परियोजना के सफल प्रयासों की सराहना की। वे ग्राम इमलिया में विभिन्न स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्यों से रूबरू हुए।

उन्होंने डीपीआइपी के जरिए उन्हें उपलब्ध आर्थिक सहायता और उनके जीवन में आए बदलाव के बारे में बातचीत की। रुहल ने महिला स्वयं सहायता समूहों की उत्पादित विभिन्न सामग्री की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। डीपीआइपी के जरिए स्वयं सहायता समूहों की सदस्य इन महिलाओं ने संगठित होकर आत्मनिर्भरता की ओर सफलतापूर्वक कदम बढ़ाए हैं और पारिवारिक जिम्मेदारियों में अपनी सशक्त भागीदारी निभा रही हैं। अपने घरों की चौखट से बाहर आकर ये महिलाएं विभिन्न आजीविका गतिविधि का बेहतर संचालन करना सीख चुकी हैं। मासिक आमदनी में औसतन दो से तीन हजार तक का इजाफा हुआ है। इससे उनके परिवार का जीवन स्तर सुधरा है।

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में विश्व बैंक प्रमुख ओनो रुहल ने 13 स्वयं सहायता समूहों को आइसीआइसीआई बैंक और सेंट्रल बैंक आफ इंडिया की ओर से करीब 10

लाख रुपए राशि के बैंक लिंकेज संबंधी स्वीकृति-पत्र मौके पर ही दिए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में हितग्राही महिलाओं ने अपने जीवन में आए सुखद बदलाव के अनुभवों को साझा किया। डीपीआइपी का दूसरा चरण प्रदेश में नवंबर, 2009 से शुरू हुआ है। डीपीआइपी के जरिए प्रदेश के 14 जिलों के 53 विकास खंड के 2,900 गांवों में आजीविका गतिविधियां संचालित हैं। परियोजना के तहत 29670 स्वयं सहायता समूह गठित हैं।